1400—2300) have since been promoted to Grade-I of DASS in the pay scale of Rs. 1640—2900. Grade I Officials of DASS have scope of promotion to DANICS who in turn are promoted to the I.A.S.

(c) and (d) The Delhi Administration have reported that due to technical nature of duties of the post of Food Inspector, specific qualifications are prescribed for their recruitment which *inter-alia* include:

— a Medical Officer incharge of health administration of a local area/or

— a graduate in medicine with one month's training in food inspection and sampling work/or

— a graduate in Science with Chemistry as one of the subjects or a graduate in Agriculture or Public Health or Pharmacy or in Veterenary Science or a graduate in Food Technology or Dairy Technology or a diploma in Food Technology or Dairy Technology.

No comparison can therefore be drawn between the two streams. Moreover, in the Prevention of Food Adulteration Department there is a different hierarchy of posts as under:—

	No. of posts	Scale
1. Food Inspector	50	Rs. 1400—2300
2. Asstt. Local (Health) Authority	5	Rs. 2000—3500
3. Local (Health) Authority	5	Rs. 3000 4500
4. Deputy Director (Technical)	1	Rs. 3700—5000

Under the existing Recruitment Rules for these posts, the post of Deputy Director (Technical) is filled by promotion from the Local Health Authorities, Local Health Authority from Assistant Local Health Authorities and Assistant Local Health Authorities from Food Inspectors.

1984 के दंगों में प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्था

1411. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फारलार्न एमबिट्टर्ड दे ट्रज आन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रशासन द्वारा 1984 के दंगों में प्रभावित हुये व्यक्तियों के लिये अब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । लगभग 80 परिवारों को, जिन्होंने दिल्ली की सीमा पार कर ली थी, दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने दिल्ली वापस जाने के लिये मनाया ।

(ग) रोहिणी में दंगा प्रभावित परिवारों को, जिनका समाचार में उल्लेख किया गया है, राहत देने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं । दिल्ली में 1984 के दंगों में प्रभावित हुये परिवारों को राहत तथा पुनर्वास देने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये उपाय भी संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

रोहिणी में दंगे से प्रभावित उन परिवारों के लिए राहत उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाए किए गए जिनके बारे में 23 मार्च, 1991 को इंडियन एक्सप्रेस में "फारलार्न एमबिट्टर्ड दे ट्रूज आन" शीर्षक के अन्तर्गत लेख प्रकाशित हुआ था :—

(I) प्रत्येक परिवार को 18 वर्ग मीटर के वैकल्पिक विकसित प्लाट का आवंटन।

(II) दिल्ली कापरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा पहली तथा दूसरी ऋण किश्त के रूप में प्रत्येक दंगा पीड़ित परिवार को 10,000 रु० की अदायगी।

2. दिल्ली में 1984 के दंगों के शिकार हुए लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए उपायों में मृत्यु, घायल तथा आवास इकाइयों के क्षति ग्रस्त होने के मामले में अनुग्रह सहायता देना, विधवाओं तथा बूढे व्यक्तियों को तदर्थ राहत पेंशन देना, स्कूल और कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देना, लड़कियों की शादी तथा विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता देना, आवासों का आवंटन करना, विधवाओं/बच्चों को रोजगार देना, गैर-बीमा त व्यापारिक सम्पत्ति की क्षति होने पर वित्तीय सहायता देना और दंगा पीड़ित परिवारों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देना शामिल।

पाकिस्तान के पास मौजूद प्रक्षेपास्त्र-प्रक्षेपक

1412. श्री राम जेठमलानी :

सरदार अजीत सिंह अरोड़ा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1991 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पाक हैज मिसाइल लांचर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने अपने वार्षिक रक्षा बजट में वृद्धि करने के बारे में हाल ही में घोषणा की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के दूसरे सीमा क्षेत्र पर स्थित चीन ने भी अपने रक्षा-बजट में वृद्धि करने की घोषणा की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) 1991-92 के बजट आबंटन में पाकिस्तान ने प्रतिरक्षा के लिए 70 अरब 95 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए हैं जो कि पिछले वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा के लिए किए गए आंबटन के मुकाबले में 11 प्रतिशत अधिक है। चीन ने 1991 के अपने बजट में 32 अरब 51 करोड़ आर०एम०बी० प्रतिरक्षा के लिए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष इस मद पर खर्च किए गए थे, 12 प्रतिशत अधिक है।

भारत की सुरक्षा से किसी भी तरह ताल्लुक रखने वाले घटनाओं पर सरकार बराबर निगाह रखती है, ताकि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती है।

"मुस्लिम्स स्टार्ट फलीइंग काश्मीर वैली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1413. श्री राम जेठमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च 1991 के "हिन्दू" में "मुस्लिम्स स्टार्ट फलीइंग काश्मीर वैली" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;